

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 1 आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण
उ०प्र०। | 4 जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ०प्र०। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2024

विषय:- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी।

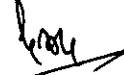
महोदय,

कृपया भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-आई/555829/2024-8-3099/282/2023 दिनांक 07.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-516/78-1-2024-1099/418/2019 दिनांक 01.04.2024 के क्रम में कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये हैं। अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० स्टेट ब्रॉड बैंड कमेटी (यू.पी.एस.बी.सी.) की दिनांक 10.11.2024 को प्रस्तावित बैठक में समीक्षा की जायेगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये

गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 07.05.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कृत कार्यवाही की अद्यतन सूचना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रत्येक दशा में आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(महेन्द्र प्रसाद भारती)

विशेष सचिव

प्रतिलिपि:- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में अभिकरणों से प्राप्त संकलित सूचना शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(महेन्द्र प्रसाद भारती)

विशेष सचिव

१०

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 4. जिलाधिकारीनियंत्रक प्राधिकारी/,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2024

विषय:- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-516/78-1-2024-1099/418/2019 दिनांक 01.04.2024 एवं उसके साथ संलग्न संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 (अनुलग्नकों सहित छायाप्रतियाँ संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराया गया है कि भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा निम्नवत् संशोधन/समावेशन किया गया है:-

(1) किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में लाइसेंसधारी, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह समुचित प्राधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिये तार सेवा को बहाल करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के बदले भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा। इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीस या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

(2) मार्ग फर्नीचर से विद्युत, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपत्ति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के मशीन के लिए प्रयुक्त पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।

(3) लाइसेंस धारक के पास कई स्थलों के लिये एकल आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्मॉल सेलों की स्थापना हेतु तदनुसार कई स्थलों के लिए एकल अनुमति जारी करने के लिए उचित उपबन्ध करेगा।

(4) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्मॉल सेलों की स्थापना की अनुमति देंगे और अनुसूची के भाग-1 या भाग-111 के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन भवनों और संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की स्थापना के लिये कोई प्रशासनिक फीस या प्रतिकर नहीं लेंगे, परन्तु कि ये प्रभार वास्तविक आंकड़े के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई बिजली (उद्योग टैरिफ के अनुसार), फिक्स्चर आदि के लिये लगाये जायेंगे और लाईसेंसधारी स्मॉल सेल की तैनाती के दौरान हुये नुकसान को बहाल करेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में संशोधन संबंधी दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुपालन के संबंध में यथावश्यकता नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

2630082/2023/00 0 -1

794

ANNEXURE - I

उत्पत्ति नं. सी.एन. 21634139

REGD. No. O. L. 23604/89



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.डी.एन. नं. 06082023-247923
CG-DL-E-06082023-247923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]
No. 455]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 594(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 10, धारा 12 और धारा 15 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के छंद (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार विधायक, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विधायक बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन विधायकों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) विधायक, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार मार्ग के अधिकार विधायक, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विधायक कहा गया है) के विधायक के लिये लागू पश्चात् निम्नलिखित विधायक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'9 क. अस्थायी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना - (1) किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के अतिरिक्त होने की स्थिति में तापसंवेद्यता, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना अतिरिक्त हो गई है तो वह संपुष्टि अधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए तार सेवा

2630082/2023/00. 0 -1

2. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

को वहात करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के वदते भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा।

(2) इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीम या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (5) में-

(क) शब्द और अंक "नियम 10ख" के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 10क और नियम 10ख" रखे जाएंगे;

(ख) चंठ(ग) के पश्चात् निम्नलिखित चंठ अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(घ) "नाग फर्नीचर" से विद्युत, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, शार्वजनिक भूतिकाता, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपत्ति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के संरचना के लिए अनुमत पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।"

4. उक्त नियमों के नियम 10क में-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(1क) नाइसंसधारक के नाम कई स्थलों के लिए एकल आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्थलों में स्थापना हेतु तदनुसार कई स्थलों के लिए एकल अनुमति जारी करने के लिए उचित उपबंध करेगा।"

(ख) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्थान में स्थापना की अनुमति देगे और अनुमूची के भाग-I या भाग-III के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन पवनों और संरचनाओं पर स्थान में स्थापना के लिए कोई प्रामाणिक फीम या प्रतिकर नहीं लेंगे।

परंतु कि वे प्रभार वास्तविक आंकड़े के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई निजनी (उद्योग डेरिफ के अनुसार), फिक्स्चर आदि के लिए लगाए जाएंगे और नाइसंसधारी स्थान में स्थापना की तैयारी के दौरान हुए नुकसान को वहात करेगा।"

5. उक्त नियमों की अनुमूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुमूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"अनुमूची

[नियम 5(3), 6(1ख), 6(2)(क), 6(3), 9(3), 9क(2), 10(2), 10(3)(क), 10क(2), 10क(4), 10क(5)]

नियम	पर	राशि
(1)	(2)	(3)
भाग-I		
शब्द		
5(3)	भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर
9(3)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	(i) बोनाइस टावर लगाने के लिए दस हजार रुपये (ii) भूमि के ऊपर तार लाइन की स्थापना के लिए एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर। (iii) खंभों की स्थापना के लिए, स्थान में स्थापना की स्थापना के लिए, अचल संपत्ति पर निहित या उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए शुल्क।

2630082/2023/00 0-1

भाग II-खण्ड 3(i)		घाट का स्तर पर : अज्ञात	3
		(iv) अंशों की स्थापना के लिए, नृपति सेत और तार मानन की स्थापना के लिए, अन्नत संपत्ति पर विहित या अनुचित केंद्रीय प्राधिकरण समुचित के अज्ञात समुचित प्राधिकरण के निर्देशन या ध्यान के लिए प्रति पोर एक दुआर ह्ये।	
9 फ (2)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।	
10 फ (2)	भारत कर्षण का उपयोग करते हुए नृपति सेत और तार मानन की स्थापना के लिए	शून्य।	
10 ज (5)	समुचित केंद्रीय प्राधिकरण के विहित या कर्षण संपत्ति अज्ञात संरचनाओं पर नृपति सेतों की स्थापना के लिए	शून्य।	
भाग-II-खण्ड 3(ii)			
6(2)(अ)	सांख्यिकीय द्वारा प्रति को दृष्टान करने की प्राधिकृत निर्देशन करने का उन्नत नहीं होने पर समुचित तार अवसंरचना की स्थापना।	यदि केंद्रीय नोक निर्माण विभाग द्वारा उन्न क्षेत्र के लिए कोई तर निर्धारित नहीं की गई हो तो अन्नत संपत्ति को उन्न क्षेत्र के लिए केंद्रीय नोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित तर के अनुसार या उन्न क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित तर के अनुसार अन्नत संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि।	
6(3)	सांख्यिकीय द्वारा प्रतिपूर्ति को दृष्टान करने की प्राधिकृत निर्देशन का उन्नत दिया है वहां समुचित तार अवसंरचना की स्थापना के साधने में निष्पादन हेतु सुरक्षा के रूप में एक गांठी।	अन्नत संपत्ति को उन्न क्षेत्र के लिए केंद्रीय नोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित तर के अनुसार या उन्न क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित तर के अनुसार पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि का 20 प्रतिशत यदि केंद्रीय नोक निर्माण विभाग द्वारा उन्न क्षेत्र के लिए कोई तर निर्धारित नहीं की गई हो।	
10 (3)(क)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	अन्नत संपत्ति को उन्न क्षेत्र के लिए केंद्रीय नोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित तर के अनुसार या उन्न क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित तर के अनुसार पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि केंद्रीय नोक निर्माण विभाग द्वारा उन्न क्षेत्र के लिए कोई तर निर्धारित नहीं की गई हो, इसके अज्ञात सांख्यिकीय स्थापित तार और तार माननों की स्थापना के लिए अंशों को स्थापित करने के साधने में हूं प्रति की पर्याप्त होगा।	
भाग-III अतिकर			
6(1घ)	समुचित तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।	
9 फ(2)	अज्ञात भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।	
10(2)	भूमि के ऊपर अवसंरचना की स्थापना	यदि ऐसी संपत्ति का उपयोग किसी अन्य उद्योग के लिए नहीं किया जा सकता है तो उपयुक्त प्राधिकरण के साधारण आदेश, द्वारा तर निर्दिष्ट कर प्रस्ता है। तथापि, नृपति सेत और तार माननों की स्थापना हेतु अंशों की स्थापना के लिए प्रतिशत शून्य होगा।	

2630082/2023/00 0-1

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY		(PART II—Sec. 3(ii))
10 क (4)	स्मान् वेस की स्थापना के लिए मार्ग कर्तव्य का उपयोग	(i) स्मान् वेस की स्थापना के लिए मार्ग कर्तव्य के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग मीटर की संख्या और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ग मीटर की संख्या स्पष्ट; (ii) तार तानन की स्थापना के लिए प्रति मार्ग कर्तव्य के अनुसार एक मीटर प्रति वर्ग।
10 क (5)	संयुक्त केंद्रीय प्राधिकारियों से विहित या उनके नियंत्रण में बल कक्षा संरचनाओं पर स्मान् वेसों की शैली के लिए	शून्य।

(का. सं. 2-6/2023-नीति)

सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिलेखना सा.का.नि. 1070 (अ.) तारीख 15 नवंबर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और नवम्बर सा.का.नि. 407 (अ.) तारीख 21 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 749 (अ.) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 और सा.का.नि. 635 (अ.) तारीख 17 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2023

G.S.R. 594(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely:—

- (1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—
"9A. Establishment of temporary overground telegraph infrastructure. — (1) In case of damage of any existing underground telegraph infrastructure for any reason, the licensee, whose existing underground telegraph infrastructure is damaged, may temporarily establish the overground telegraph infrastructure, in lieu of the damaged underground telegraph infrastructure, to restore the telegraph service for the period of sixty days from the date of reporting of damage of the infrastructure to the appropriate authority.
(2) No fee or compensation shall be charged by the appropriate authority for the establishment of temporary overground telegraph infrastructure under this rule".
- In rule 10 of the said rules, in sub-rule (5)—
(a) for the word and figure "rule 10B", the words and figures, "rule 10A and rule 10B", shall be substituted;
(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
(d) "street furniture" means post or pole used for electricity, street light, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole or any other structure or contrivance of such nature established over the property of an appropriate authority.

2630082/2023/00 0-1

798

[भाग II—खण्ड 3(i)]

घरत का राजपत्र : समाचार

5

4. In rule 10A of the said rules,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The licensee shall have the option of submitting single application for multiple sites and appropriate authority shall make due provisions for accepting such applications and issuing single permission for multiple sites accordingly for establishment of small cells."

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The appropriate central authorities shall permit deployment of small cells and shall charge no administrative fees or compensation for deployment of small cells on buildings and structures vested in or under their control as per Part-I or Part-II of the Schedule:

Provided that the charges shall be levied for power (as per industry tariffs), fixtures etc. provided by building owners as per accruals and licensee shall restore the damage done during deployment of small cells."

5. For the Schedule of the said rules, the following schedule shall be substituted, namely:-

"THE SCHEDULE

[See rules 5 (3), 6 (1B), 6 (2) (c), 6 (3), 9 (3), 9 A (2), 10 (2), 10 (3) (a), 10A (2), 10A (4), 10 A (5)]

Rule	Item	Amount
(1)	(2)	(3)
Part-I Fee		
5(3)	For establishment of underground telegraph infrastructure	One thousand rupees per kilometer.
9(3)	For establishment of overground telegraph infrastructure	(i) Ten thousand rupees for establishment of mobile towers (ii) One thousand rupees per kilometre for establishment of overground telegraph line. (iii) Nil for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate central authority (iv) One thousand rupee per pole for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate authority, other than appropriate central authority.
9 A (2)	For Establishment of temporary overground Telegraph Infrastructure.	Nil.
10A (2)	For installation of small cells and telegraph line using the street furniture	Nil.
10 A (5)	For the deployment of small cells on building or structures vested in or under the control of appropriate central authorities.	Nil.
Part-II Charges for restoration		
6(2)(a)	Establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is not given by the licensee to discharge the responsibility to restore the damages	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area.
6(3)	Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is given by the	20 percent of the sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area.

2630082/2023/00 0 -1

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—Sec. 3(ii)]

6		
	licensee to discharge the responsibility to restore the damages	If no rate has been prescribed by central public works department for that area.
10(3)(a)	Establishment of overground telegraph infrastructure	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area, further, licensee shall restore the damage incurred in case of establishment of poles for installation of Small Cells and telegraph line.
Part-III Compensation		
6(1B)	Establishment of underground telegraph infrastructure	Nil.
9 A(2)	For Establishment of temporary over ground Telegraph Infrastructure.	Nil.
10(2)	Establishment of Over Ground Infrastructure	Rates as the appropriate authority may, by general order, specify, if such property cannot be used for any other purpose. However, for establishment of poles for installation of small cells and telegraph line, compensation shall be Nil.
10A (4)	Usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line	(i) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture. (ii) For installation of telegraph line: One hundred rupees per annum per street furniture.
10 A (5)	For the deployment of small cells on building or structures vested in or under the control of appropriate central authorities.	Nil.

(F. No. 2-6/2023-Policy)

SUNIL KUMAR VERMA, Jr. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification O.S.R. 1070 (E), dated the 15th November, 2016 and subsequently amended vide G.S.R. 407 (E), dated the 21st April, 2017, O.S.R. 749 (E), dated the 21st October, 2021 and G.S.R. 635(E), dated the 17th August, 2022.